प्रेस विज्ञप्ति

21 फरवरी, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व कुलजीत सिंह नागरा, सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बयान :–

न मोदी–न माया, यूपी को कांग्रेस–सपा गठबंधन भाया

हार सामने देख मोदी घबराए– भद्दी भाषा, झूठे बोल भी काम न आए

किसान से विश्वासघात, रोजी–रोटी पर कुठाराघात, यही है मोदी के 'मन की बात'

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस–सपा गठबंधन विजय की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर भाजपा की सुनिश्चित हार देख प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी बौखलाए, झुंझलाए व घबराए हैं।

स्वघोषित दत्तक पुत्र नरेन्द्र मोदी – न गंगा का, न गाँव का

प्रधानमंत्री जी अपनी अकर्मण्यता का दाग अंततः नफरत व बंटवारे के प्रचार संस्थान के प्रधानाचार्य बनकर धोना चाहते हैं। सच मानें तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिये प्रजातंत्र के पवित्र यज्ञ में सबसे ज्यादा आहूतियाँ यू.पी. ने दी हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदीजी ने सबसे ज्यादा आहत यू.पी. को किया है।

यू.पी ने स्वतन्त्रता सेनानियों, कलाकारों, कलमकारों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों जैसे अनेकों सपूतों को जन्म दिया है मगर यू.पी की मिट्टी ने कभी झूठों को पैदा नहीं किया। मोदीजी, आप किस मिट्टी के बने हैं? माँ गंगा की सौगन्ध खाते हैं, उसे चोट पहुँचाते हैं। किसानों की कसमें खाते हैं, उसे धोखा दे जाते हैं। **सत्ता के ढाई साल और यू.पी. के 73 सांसदों के काम का हिसाब पूछें तो नफरत और बंटवारे का मुखौटा लगाते हैं।** इतना ही नहीं मौत को भी धर्म के आधार पर बाँटकर बस वोट पाना चाहते हैं।

मोदी जी के जुमलों की यही सच्चाई है। विपक्ष और किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा, 'फसलों के दाम दे दो'। पर वो कहते हैं, 'फसल बर्बाद हो जाने दो, बीमा दूंगा'। देश के नागरिक कहते हैं, 'अच्छी जिंदगी दीजिए'। वो कहते हैं, 'मर जाने दो, 1 लाख का बीमा दूंगा।' लोग कहते हैं, 'जिंदगी जीने के लिए रोटी–रोजगार दीजिये'। मोदी जी कहते हैं, 'शमशान और कब्रिस्तान दूंगा'। मोदी जी, **लोगों को 'अच्छे दिन' के दीदार कराइए, मौत के द्वार मत पहुँचाइए।**

किसान से धोखा – लागत+ 50% मुनाफा खारिज व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी नामंजूर

आज समूचा उत्तर प्रदेश और उसके **2 करोड़ 32 लाख** किसान परिवार **भाजपाई झूठ का हिसाब** करना चाहते हैं ।

उत्तर प्रदेश, देश का **सबसे ज्यादा गेहूँ** उत्पादन करता है, जो देश के कुल उत्पादन का **32%** है, यानि लगभग **283 लाख टन**। **धान** के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, **देश में दूसरे स्थान** पर है, यानि कुल उत्पादन का 12.5% या **125 लाख टन।**

साल, 2014 में मोदीजी ने कसम उठाई कि वो फसल की कीमत पर 50% मुनाफा देंगे व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। **प्रधानमंत्री बनकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथपत्र दिया कि किसान की लागत पर 50% मुनाफा देना संभव नहीं।** इस शपथपत्र की प्रतिलिपि

संलग्नक **A1** है। यही नहीं, आरटीआई के जवाब में 50% मुनाफा व स्वामीनाथन आयोग, दोनों को ही खारिज कर डाला, जिसकी कॉपी संलग्नक **A2** है।

इससे भी शर्मनाक व अन्यायपूर्ण बात यह है कि **उत्तर प्रदेश 'नॉन डीसेन्ट्रलाईज्ड प्रिक्योरमेन्ट स्टेट' है** यानि कि किसान के अनाज की **खरीद की सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार** की है। पर केंद्र की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के किसान का अनाज **'समर्थन मूल्य'** पर नहीं खरीदती।

शर्मनाक बात यह है कि जहाँ 2016–17 में देश में 229.30 लाख टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार ने खरीदा वहीं **उत्तर प्रदेश में मात्र 7.97 लाख टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा गया अर्थात् लगभग 3.47%।** इसी प्रकार पूरे देश में केंद्रीय सरकार ने 2016–17 में 223.12 लाख टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदा, परंतु हैरत की बात है कि **उत्तर प्रदेश के किसान से मात्र 6.37 लाख टन, अर्थात् मात्र 2.85% खरीदा गया।** विडम्बना यह है कि लागत+ 50% मुनाफा देना तो दूर, उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा देकर उनसे समर्थन मूल्य पर अनाज भी मोदी सरकार नहीं खरीदती।

Procurement of Wheat in Uttar Pradesh

Marketing Seasons	Wheat Production U.P. (Lakh Tonne)	Wheat Procurement - U.P. (Lakh Tonne)	All India Wheat Procurement (Lakh Tonne)	U.P. Procurement as % of Total Procurement
2014-15	224.17	6.28	280.23	2.24%
2015-16	283.65	22.67	280.88	8.07%
2016-17	--	7.97	229.30	3.49%

Procurement of Rice in Uttar Pradesh

Marketing Seasons	Paddy Production U.P. (Lakh Tonne)	Paddy Procurement - U.P. (Lakh Tonne)	All India Paddy Procurement (Lakh Tonne)	U.P. Procurement as % of Total Procurement
2014-15	121.68	16.98	320.40	5.29%
2015-16	125.09	29.10	341.42	8.5%
2016-17	--	6.37	223.12	2.85%

दिनांक 02.01.2017 की स्थिति के अनुसार

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद राज्यों द्वारा **'समर्थन मूल्य' के ऊपर दिया जा रहा 'बोनस' बन्द करा दिया।** और तो और, मोदी सरकार के **'गन्ने की कीमत तय करने वाले आयोग'** ने हाल ही में **यह सिफारिश की है कि राज्य द्वारा घोषित किया जाने वाला गन्ने का अतिरिक्त मूल्य तुरन्त राज्यों से बन्द करवा दिया जाना चाहिए जिसे 'स्टेट एडवाइस्ड प्राइस' कहा जाता है।** केंद्रीय सरकार अभी भी गन्ने का 'फेयर एण्ड रिमेन्युरेटिव प्राइस' निर्धारित करती है जो कि 230 रु. प्रति क्विंटल 9.5% 'रिकवरी लेवल' पर निर्धारित है। वहीं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया 'स्टेट एडवाइज्ड प्राइस' 305 रु. प्रति क्विंटल है। **शर्मनाक बात तो यह है कि मोदी सरकार का आयोग भी उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसान की उत्पादन लागत 255 रु. प्रति क्विंटल मानता है पर केंद्रीय सरकार यूपी के गन्ने की कीमत मात्र 230 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित करती है। क्या मोदीजी इसका जवाब देंगे?**

नोटबंदी या विकासबंदी

नोटबंदी के दुष्परिणामों से उत्तर प्रदेश का हर शहर और उद्योग मंदी के भयावह दौर से गुजर रहा है। अलीगढ़ के **'ताला उद्योग'** पर ताला लग गया है, आगरा का **'जूता एवं पेठा उद्योग'**, कानपुर का **'चमड़ा उद्योग'**, मिर्जापुर भदोही का **'कालीन उद्योग'**, बनारस का **'साड़ी व्यापार'**, खुर्जा के **'चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग'**, मेरठ का **'रेवड़ी उद्योग'**, लखनऊ का **'चिकनकारी उद्योग'**, बरेली का **'मांझा व बांस फर्नीचर उद्योग'**, मुरादाबाद का **'पीतल उद्योग'** जैसे सभी स्थानीय रोजगार ठप्प हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। पूरे देश में करीब 2.25 करोड़ मध्यम एवं लघु उद्योग हैं, जिनमें से बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में हैं। नोटबंदी के कारण ये सारे उद्योग मंदी की मार झेल रहे हैं और बंद होने के कगार पर हैं। नोटबंदी की वजह से उत्तर प्रदेश का **'खांडसारी एवं कोल्हू उद्योग'** पूर्णतया चौपट हो गया है। बेरोजगारी दूर करने के अपने वायदे पर श्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। **2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने वर्ष, 2016 में कुल 1,40,000 युवाओं को ही रोजगार दिया** (सन, 2016 भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार)।

भाजपा और अपराध का 'चोली दामन' का साथ

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की अलौकिक और पवित्र भूमि को 'अपराधियों का गढ़' कहकर लगातार बदनाम कर रहे हैं।

देश के गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह क्या जवाब देंगे कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो क्या यूपी में प्रतिवर्ष 7,610 'हत्याएँ' और 7,964 'हत्या के प्रयास' नहीं हुआ करते थे? आज अखिलेश सरकार में हत्या के प्रकरण आधे रह गये हैं अर्थात् 4,732 और हत्या के प्रयास 4,897, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी साल, 2001 की तुलना में काफी बढ़ी है। हमारा मानना है कि कांग्रेस सपा गठबंधन और अधिक तेजी से अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा।

दुर्भाग्य से मोदी जी यूपी को लगातार 'बलात्कार व महिला उत्पीड़न' के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। यूपी जानना चाहता है कि **क्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4,391 बलात्कार देश में सबसे ज्यादा नहीं है? दूसरे नंबर** पर भाजपा शासित राज्य **महाराष्ट्र** है जहाँ प्रतिवर्ष **4,114 अबलाओं** से होते बलात्कार का शर्मनाक आंकड़ा है। **तीसरे नंबर पर भाजपा शासित राजस्थान** है, जहाँ बलात्कारों की संख्या 3,644 है, जबकि यूपी की आबादी इन राज्यों से दुगनी और तीन गुनी है। **'महिलाओं से छेड़छाड़ व इज्जत पर हमले'** वाले अपराधों में भी **भाजपा शासित महाराष्ट्र पूरे देश में 11,713 प्रकरणों के साथ पहले नम्बर पर है। दूसरे नम्बर** पर **8,049 प्रकरण** के साथ भाजपा शासित **मध्यप्रदेश** है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता के तहत होने वाले **'कुल यौन अपराधों'** में भी **भाजपा शासित महाराष्ट्र 16,989 प्रकरणों के साथ देश में पहले स्थान पर है** और भाजपा शासित **मध्यप्रदेश 12,887 प्रकरणों** के साथ **दूसरे स्थान** पर है। मोदी जी, अगर 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' की रिपोर्ट (जो कि गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह जारी करते हैं) पढ़ लेते, तो शायद इतना झूठ न बोलना पड़ता।

नकारात्मकता निराशा का परिचायक है। इसीलिए यूपी की हार जितनी नज़दीक और बड़ी दिख रही है, मोदी जी के भाषण और भाषा, उतनी भद्दी हो रही है। यूपी सत्य और संस्कार, अदब और एतबार का प्रदेश है। इसीलिए मोदी जी यूपी को 'Division' देना चाहते हैं, और कांग्रेस–एसपी यूपी को एक नया 'Vision'।